हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली

*१८६. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २० सितम्बर, १६५५ को दिये गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, दिल्ली की भावी योजना निश्चित करने के लिये जो विभागीय विशेषज्ञों की विभागीय समिति बनाई गई थी उसने क्या प्रगति की है ;

(ख) उस फैक्टरी में इस समय किस प्रकार का काम किया जा रहा है और किस व्यक्ति की देख रेख में आजकल यह काम हो रहा है ; और

(ग) फैक्टरी म कितने कर्मचारी और श्रमिक हैं और उन पर आजकल मासिक व्यय कितना होता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) समिति की पहली बैठक १२ अक्तूबर, १६५५ को हुई । उसके टेकनिकल सदस्य आजकल जरूरी तथा पूरी जांच कर रहे हैं ।

(ख) फैक्टरी के पास Pre-stressed and precast concrete के टुकड़े और लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों वगैरा की जो मांगें आ चुकी हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है । यह काम फैक्टरी के जनरल मैनेजर की देख भाल में हो रहा है । वे केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग में Executive Engineer हैं।

(ग) फैक्टरी में आजकल ७० कर्मचारी तथा ४०० श्रमिक काम करते हैं । माहवारी खर्च लगभग ४४,००० रुपये है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि बसाखा सिंह और उनके साथियों ने जो सामान बनाया था वह कितना था, उसका मूल्य क्या था और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब से इस हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी का निर्माण हुआ है तब से अब तक सरकार को कितना नुकसान देना पड़ा है और इस पर कुल कितनी लागत लगी है, और अब जो भविष्य के लिये कर्मचारी लगे हुये हैं उनको कितना वेतन वगैरह दिया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस फैक्टरी की हिस्ट्री कई दफा हाउस के सामने आ चुकी है और उस पर बहस हो चुकी है । । पहले यह हेल्थ मनिस्ट्री के पास थी, फिर प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के पास रही, थोड़ा समय हुआ कि अब यहां आई है । इसलिये इस सारी डिटेल की आप मुझ से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं बता सकूं कि कौन कौन सी चीज किस किस वक्त बनी और उसका क्या हुआ । यह बड़ी डिटेल्स हैं । इनके लिये नोटिस चाहिये ।

WRITTEN ANSWERS

Aluminum

*165 { Shri M. S. Gurupadaswamy : Shri S. K. Razmi :

Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state the steps Government have taken or propose to take to increase the production of Aluminium in the country?

The Minister of Commerce and Industry and Iron and Steel (Shri T. T. Krishnamachari) : The existing manufacturers of Aluminium ingots have been granted licences to increase their capacity from 7,500 tons to 20,000 tons per annum; facilities to import plant and machinery, release of controlled commodities such as steel are being given. Besides, a Committee of Experts has recently been set up by Government to examine and report *inter alia* on possible sites for additional capa-

ity for aluminium in the country, having regard to the availability of bauxite, power and other facilities required.

Central Committee on Land Reforms

*175. **Shri N. B. Chowdhury:** Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 2381 on the 29th September, 1955 and state the views expressed by the Central Committee for Land Reforms with regard to the rights to be conferred on the sharecroppers of West Bengal?

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra): The discussions in the Central Committee for Land Reforms are of informal and confidential nature and it will not be in public interest to disclose them.

French Possessions in India

*184. **Shri N. M. Lingam:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 470 on the 5th August, 1955 and state:

(a) whether negotiations for the *de jure* transfer of the former French possessions in India have commenced; and

(b) if so, the stage at which the matter stands at present?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Anil K. Chanda): (a) Yes.

(b) A draft treaty of cession of the French Settlements in India was handed over by the Government of India to the French Ambassador in New Delhi in May, 1955. Our Ambassador in Paris is pursuing the matter further.

कम्बोडिया और लाओस में भारतीय कानसुलेट

*१९० **श्री श्रीनारायण दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया और लाओस में क्रमशः स्थापित पोलीटीकल मिशन और कॉनसुलेट जनरल का दर्जा ऊपर उठाने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निश्चय किया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). २२ अप्रैल, १९५५ से कम्बोडिया में खास मिशन का दर्जा बढ़ा कर दूतावास कर दिया गया था । लाओस में कॉनसुलेट जनरल का दर्जा बढ़ाने के सवाल पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

Gift of a Planetorium

*192. **Sardar Hukam Singh:** Will the **Prime Minister** be pleased to state.

(a) whether the Government of Democratic German Republic has made a gift to the Government of India of a planetorium which is an exhibit in the Industries Fair in Delhi; and

(b) if so, where this is going to be installed?

The Parliamentary Secretary to the Minister of External Affairs (Shri Sadath Ali Khan): (a) and (b). Yes. The Planetorium will continue where it is till a more suitable place is found for it.

Milan Samples Fair

*193. **Shri S. C. Samanta:** Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1290 on the 29th September, 1955 and state:

(a) whether the required information about the Indian Pandal at the Milan Samples Fair held in April, 1955, has since been received from our Embassy in Italy;

(b) if so, whether a statement will be laid on the Table of the House; and

(c) whether the Officer who was in charge of the Indian Exhibits in the Milan Samples Fair, is still working in the Indian Embassy there?

The Minister of Commerce (Shri Karmarkar): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Shortly.

(c) No, Sir.

Handloom Co-operative Societies

71. **Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) the total number of handloom weavers who are working under the Hand loom Co-operative Societies in the various States at present;

(b) the total amount of share (capital provided to the weavers so far Statewise) out of the fund collected from cloth cess;

(c) the total amount of working capital granted to the Co-operative Societies in each State; and